और फिर :

> "पूर्ण मजदूरी सामान्य नियम और पार्टी होगी इस पर आपत्ति जताते हुए परिस्थितियों को स्थापित करना होगा प्रस्थान की आवश्यकता"
>
> पूर्वोक्त दृश्य तब उनके द्वारा दोहराया गया है में आधिपत्य **G.T. लाड और अन्य** वी. **रसायन और फाइबर्स इंडिया लिमिटेड."**

(17) उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे इस सबमिशन में कोई योग्यता नहीं मिली है श्री सिबल का भी.

(18) यह कानून का प्रस्ताव है कि रिट का प्रयोग करते समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत क्षेत्राधिकार श्रम न्यायालय / औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया पुरस्कार, थि·s कोर्ट अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठेगा. रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, इस पुरस्कार के साथ हस्तक्षेप करने में न्यायालय को उचित ठहराया जाएगा रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है. यह होगा यदि निष्कर्ष वापस आ गए तो पुरस्कार के साथ हस्तक्षेप करने में भी उचित होगा श्रम न्यायालय द्वारा बिना किसी सबूत के आधारित हैं. यह भी होगा यदि तथ्यों के निष्कर्ष दिखाई देते हैं तो पुरस्कार के साथ हस्तक्षेप करना उचित है रिकॉर्ड के चेहरे पर विकृत होना. यह अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी पुरस्कार के साथ केवल इस आधार पर कि कुछ साक्ष्यों पर, रिकॉर्ड किए गए एक से अलग दृश्य देना संभव होगा श्रम न्यायालय. पूरे मामले पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय यह विचार है कि पुरस्कार स्पष्ट रूप से किसी भी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है रिकॉर्ड के चेहरे पर.

(19) नतीजतन, इस रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है. वहां होगा लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है.

R.N.R.

जे.एस. नारंग, जे. के सामने

आदियामन शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (पंजीकृत ट्रस्ट) और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक -उत्तरदाता

2000 का *सीडब्ल्यूपी नं.* 11321

---

24 अगस्त 2001

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद *226*-एक संबद्धता-याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन-विधि संस्थान की स्थापना के लिए अनंतिम संबद्धता के लिए ट्रस्ट-बीसीआई और राज्य सरकार से विश्वविद्यालय की शर्तों के अनुसार, एनओसी प्राप्त-निरीक्षण समिति ने पहले से ही संबद्धता की सिफारिश की थी, लेकिन कुलपति ने इस दलील पर इनकार कर दिया कि संस्थान आवश्यक औपचारिकताओं की पुष्टि नहीं करता है-अकादमिक परिषद ने सिफारिश की है कि अगले शैक्षणिक सत्र के लिए संबद्धता दी जाए और इस बीच संस्थान आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करेगा- नवीनतम निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आलोक में संस्थान की संबद्धता पर विचार करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देते समय अनुमति दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि *15* जुलाई, *2000* की द्वितीय निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के अवलोकन पर, यह अवलोकन करना उचित है कि याचिकाकर्ताओं के मामले को *M.D.* विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार

सभी पहलुओं पर विचार करके, अनंतिम संबद्धता प्रदान करने के लिए समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है। विश्वविद्यालय की याचिका बहुत ही भ्रामक है और *16* फरवरी, *2001* के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि एक बहुत ही अनौपचारिक और सरसरी दृष्टिकोण अपनाया गया है। वास्तव में, ऐसा लगता है कि दिमाग का कोई अनुप्रयोग नहीं किया गया है।दूसरी निरीक्षण समिति द्वारा विभिन्न शीर्षों के अधीन की गई सिफारिशों की तुलना कार्यकारी परिषद द्वारा किए गए अवलोकन से पता चलता है कि दूसरी समिति की रिपोर्ट और पहली समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करने के अलावा, वास्तव में रिपोर्टों का बिल्कुल भी अवलोकन नहीं किया गया है। हालांकि, भले ही पूरी करने योग्य कमियों को उजागर किया जाता है, इसे अस्थायी संबद्धता देने के लिए शर्त पूर्ववर्ती बनाया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि ऐसी शर्तों को एक समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए जो संभव नहीं हो सकता है। दृष्टिकोण रचनात्मक और सकारात्मक होना चाहिए। कोई भी संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवित नहीं रह सकता है।

*(*पैरा *29)*

याचिकाकर्ताओं की ओर से मधु दयाल अधिवक्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव आत्मा राम।
आर.एस. टैकोरिया, प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता।

निर्णय

जे.एस. नारंग, जे.

1. याचिकाकर्ता नं। 1 एक न्यास है, जो फर्मों और समितियों के पंजीयक, तमिलनाडु के साथ संविधि के तहत और सोसायटी

पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी पंजीकृत है। यह एक पूरी तरह से मजबूत, वित्तीय स्थिति में है और इसमें एक करोड़ से अधिक की संपत्ति है, जिसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह पूरे देश में लगभग 12 कॉलेज और स्कूल स्थापित करने में सक्षम रहा है। राष्ट्रीय विधि संस्थान के नाम और शैली में एक संस्थान बनाया गया है और यह ट्रस्ट हरियाणा राज्य में एक "लॉ कॉलेज" स्थापित करना चाहता है।

2. पहली बार में एक आवेदन दिनांक 16 अप्रैल, 1998 (प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-4) रजिस्ट्रार, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक ("M.D. विश्वविद्यालय"), उत्तरदाता को संबोधित किया गया था। इसके जवाब में, M.D. विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है कि आवेदक को पहली बार में बार कॉन्सिल ऑफ इंडिया से "अनुमोदन" और हरियाणा सरकार से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" भी प्राप्त करना चाहिए। उपर्युक्त अनुमोदन और अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा करने पर लॉ कॉलेज के संबंध में संबद्धता देने के अनुरोध पर विचार किया जाएगा। इसकी अगली कड़ी के रूप में, उपरोक्त अधिकारियों के समक्ष संबंधित आवेदन दायर किए गए थे। भारतीय विधिज्ञ परिषद ने 20 जनवरी, 1998 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में लॉ कॉलेज के निरीक्षण के लिए एक समिति नियुक्त की और उक्त समिति की रिपोर्ट पर लॉ कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 1998-99 के लिए तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम के लिए 80 छात्रों और पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम के 80 छात्रों का प्रवेश आरंभ करने की तदनुसार अनुमति दी और इस संबंध में 17 अक्टूबर, 1998 को M.D. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को संबोधित किया गया था, (Copy Annexure P-7).

3. इसी प्रकार, हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 11 जनवरी, 1999 के संचार के माध्यम से (copy Annexure P-8) "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी किया गया था हालांकि, अन्य हानिरहित शर्तों के अलावा, तीन शर्तें लगाई गईं, जो इस प्रकार हैंः-

.....

.....

(1) विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा निर्धारित सभी संबद्धता की शर्तें को ट्रस्ट द्वारा पूरा किया जाएगा।

(2) उच्च शिक्षा निदेशक के नाम पर विधिवत गिरवी रखे गए विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार बंदोबस्ती निधि का एफडीआर तुरंत इस कार्यालय को भेजा जाएगा;
(3) कॉलेज के अधिकारी सरकारी/विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती करेंगे और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करेंगे।

.....

.....

4. उपरोक्त अनुमोदन और अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर, संबद्धता प्रदान करने के लिए संशोधित आवेदन M.D. विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया गया था और आवेदन के साथ रु 50, 000 का शुल्क भी जमा किए गए। उक्त आवेदन 16 अप्रैल, 1998 को प्रस्तुत किया गया था (प्रतिलिपि अनुलग्नक, पी-4)। उपरोक्त आवेदन के अनुसरण में, एक निरीक्षण समिति का गठन किया गया था, लेकिन अज्ञात कारणों से, निरीक्षण नहीं किया गया था। कई अनुस्मारक पत्र जारी किए गए लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह भी बताया गया था कि सत्र 1998-99 के लिए विधि महाविद्यालय की स्थापना का समय समाप्त हो रहा था और इस संबंध में निवेश की गई धनराशि महाविद्यालय के प्रारंभ के रूप में उपयोगी नहीं होगी, बल्कि अन्य नुकसानों के साथ-साथ ब्याज की हानि का कारण बनेगी। याचिकाकर्ता M.D विश्वविद्यालय की ओर से विश्वविद्यालय की निष्क्रियता से

व्यथित था, और इसलिए, 1999 का सिविल रिट याचिका नं 15063 दायर की गई । उपरोक्त रिट याचिका के लंबित होने के दौरान, M.D. विश्वविद्यालय ने एक नई निरीक्षण समिति का गठन किया। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह अनुरोध किया गया था कि निरीक्षण समिति अब दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है और उसके बाद विश्वविद्यालय अगले दो सप्ताह के भीतर संबद्धता के मुद्दे को अंतिम रूप दे सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई थी कि निरीक्षण समिति याचिकाकर्ता की स्थापना का निरीक्षण करेगी और 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, लेकिन M.D. विश्वविद्यालय के प्रशासन में आसन्न परिवर्तनों के कारण संबद्धता के संबंध में अंतिम निर्णय में कुछ समय लग सकता है।

5. पक्षकारों द्वारा दिए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए, याचिका का निपटान दिनांक 28 फरवरी, 2000 के आदेश द्वारा दो निर्देशों के साथ किया गया था जो निम्नानुसार हैंः -

"..... .....

(1) नवगठित निरीक्षण समिति याचिकाकर्ता नं. 2 की स्थापना का निरीक्षण करेगी और दो सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(2) निरीक्षण समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दो महीने के भीतर, विश्वविद्यालय के सक्षम निकाय याचिकाकर्ता नं. 2 की संबद्धता के मुद्दे पर विचार करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे ।

यदि कुछ अप्रत्याशित कारणों से याचिकाकर्ता नं. 1 की संबद्धता के मुद्दे को अंतिम रूप देने में कोई देरी होती है, तब पक्षकार समय के विस्तार के लिए विविध आवेदन दाखिल करने के हकदार होंगे।"

.....

.....

6. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निरीक्षण समिति को दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी और M.D. विश्वविद्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दो महीने के भीतर अंतिम निर्णय लेना था।
7. निरीक्षण समिति ने निरीक्षण किया और रिपोर्ट जो दिनांक 4 अप्रैल, 2000 की है (अनुलग्नक पी-16 की प्रति) प्रस्तुत की । आश्चर्यजनक रूप से, विभिन्न अवलोकन करने के बाद, यह देखते हुए रिपोर्ट पर निष्कर्ष निकाला करें कि संबद्धता प्रदान करने की सिफारिशें "अकादमिक परिषद" के निर्णय पर छोड़ दी गई हैं। इस संबंध में निरीक्षण समिति द्वारा शामिल किए गए शब्दों पर ध्यान देना उचित होगा जो इस प्रकार हैंः-

   "जहां तक संबद्धता प्रदान करने की सिफारिशों का संबंध है, समिति इसे अकादमिक परिषद के निर्णय पर छोड़ देती है।"
8. M.D. विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने 30 मई, 2000 को बैठक की और लॉ कॉलेज शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले निजी प्रबंधित संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने के संबंध में निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। इस संबंध में यह संकल्प लिया गया कि कुलपति इस बात से संतुष्ट होने के बाद अस्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं कि संस्थान के पास पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं, जिसके लिए निरीक्षण समिति की प्रतिनियुक्ति की जाए। यह अजीब बात है कि निरीक्षण समिति ने कोई सिफारिश नहीं की और इसे अकादमिक परिषद पर छोड़ दिया और अकादमिक परिषद ने मामले पर निर्णय लेने के बजाय, किसी अन्य निरीक्षण समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अस्थायी संबद्धता देने के लिए कुलपति को अधिकृत किया। एक अन्य निरीक्षण समिति के गठन के कारणों का खुलासा नहीं किया

गया था और न ही इस संबंध में कोई अवलोकन अकादमिक परिषद द्वारा किया गया था।

9. तथापि, कुलपति ने एक नई निरीक्षण समिति का गठन किया जिसने 15 जुलाई, 2000 को निरीक्षण किया और विस्तृत रिपोर्ट (तारीख निर्णय योग्य नहीं) प्रस्तुत की गई। हालांकि, इसे दिनांक 15 जुलाई, 2000 प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-19 के रूप में संदर्भित किया गया है, अनंतिम संबद्धता प्रदान करने के लिए की गई वर्गीकरण संबंधी सिफारिशों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, रिपोर्ट का संबंधित भाग इस प्रकार है -

"..... .....

समिति की सिफारिश।

जहां तक प्रोविजनल संबद्धता प्रदान करने की सिफारिश का संबंध है, समिति को लगता है और यह राय है कि प्रस्तावित संस्थान/कॉलेज ऑफ लॉ को LL.B पांच साल के पाठ्यक्रम का भाग I और तीन साल के पाठ्यक्रम का भाग I w.e.f. वर्तमान शैक्षणिक सत्र i.e. 2000-2001 प्रत्येक पाठ्यक्रम (LL.B. 3 वर्ष और 5 वर्ष) में 80 सीटों की संख्या के लिए के कानून पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए पहले से ही N.O.C में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय की महाविद्यालय शाखा के पास उपलब्ध है आवश्यक प्रारंभिक बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं मिली हैं।

संस्थान/कॉलेज U.G.C., राज्य सरकार और M.D. विश्वविद्यालय, रोहतक की अनिवार्य शर्तों को पूरा करेगा जो समय-समय पर उन शर्तों के अलावा लगाया जा सकता है जिनके लिए संस्थान ने एक वचन दिया है और उन शर्तों को गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर नोटरीकृत रूप में निर्धारित किया गया है। जहां तक किसी विश्वविद्यालय के संबद्ध विधि महाविद्यालयों के प्रश्न का संबंध है, भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली, "संस्थान" शब्द के उपयोग की अनुमति नहीं देती है। इसलिए, भारतीय

विश्वविद्यालय/बार काउंसिल, नई दिल्ली और राज्य सरकार की सहमति से फरीदाबाद में प्रस्तावित विधि संस्थान का नामकरण को बदलने की सलाह दी जाती है । इस संबंध में समिति का सुझाव है कि संस्थान को संबद्धता मिलने के बाद प्रस्तावित संस्थान बार काउंसिल ऑफ इंडिया और M.D. विश्वविद्यालय रोहतक के मानदंडों की पुष्टि में "नेशनल लॉ कॉलेज, फरीदाबाद" या लॉ कॉलेज के किसी अन्य उपयुक्त नाम के रूप में नामकरण का उपयोग कर सकता है।

1. (डॉ. एल.सी. धींगरा) संयोजक

2. (डॉ. अल्लेकखान)

3. (डॉ. ए.एस. चिल्लर)

1. क्या समिति संबद्धता की सिफारिश करती है? यदि हां, तो अधिकतम छात्रों वाली कक्षाओं/पाठ्यक्रमों के नाम किस संबद्धता के लिए अनुशंसित हैं? (कृपया लगाई गई शर्तों का विशिष्ट विवरण दें जिसके लिए संबद्धता की सिफारिश की जाती है)
हां, विस्तृत रिपोर्ट अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ संलग्न है।
2. संबद्धता के विस्तार के मामले में, क्या संस्थान ने पिछली निरीक्षण समितियों द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा किया है। निरीक्षण रिपोर्ट/सिफारिशों में शर्त-वार विवरण/तुलनात्मक स्थिति दें।

चूंकि, यह विश्वविद्यालय द्वारा विधि पाठ्यक्रमों के लिए प्रारंभिक संबद्धता का मामला है, इसलिए इस स्तर पर विस्तार का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हालांकि, इस रिपोर्ट में निर्धारित सभी शर्तों का पालन प्रस्तावित लॉ कॉलेज द्वारा किया जाएगा।

1. (डॉ. एल.सी. धींगरा) संयोजक।

2. (डॉ. अल्लेकखान)

3. (डॉ. ए.एस. चिल्लर)

10. इस बीच याचिकाकर्ताओं ने हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, विज्ञान और इतिहासके विषयों में कर्मचारियों की पहचान करने के लिए "वॉक-इन-इंटरव्यू" के लिए विज्ञापन दिया था। इसके जवाब में, जिन उम्मीदवारों ने भाग लिया था और जिनका साक्षात्कार लिया गया था, उनकी पहचान तदनुसार की गई थी। इस प्रकार पहचाने गए उम्मीदवारों का M.D. विश्वविद्यालय को विधिवत सूचित किया गया था, जैसा कि 3 अगस्त, 2000 को M.D. विश्वविद्यालय को संबोधित संचार से स्पष्ट है, (अनुलग्नक पी-20 की प्रतिलिपि) । लेकिन याचिकाकर्ताओं को आश्चर्यचकित करने के लिए, कुलसचिव के लिए उप कुलसचिव (महाविद्यालय) के हस्ताक्षर के तहत 7 अगस्त, 2000 का संचार M.D. विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ। यह खुलासा करते हुए कि फरीदाबाद में विधि महाविद्यालय शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को मंजूरी नहीं दी गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस बीच 1998-99 के शैक्षणिक सत्र और 1999-2000 के शैक्षणिक सत्र को भी अनुमति दी गई थी।
11. याचिकाकर्ता पूरी तरह से असंतुष्ट थे कि निरीक्षण समिति द्वारा 15 जुलाई, 2000 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय की गई सिफारिशों के बावजूद, कुलपति ने संबद्धता देने से इनकार कर दिया।
12. दिनांक 7 अगस्त, 2000 के आदेश की प्रति अनुलग्नक पी-21 को वर्तमान रिट याचिका की चुनौती का विषय बनाया गया था। विभिन्न आधारों पर आरोपित आदेश की वैधता पर सवाल उठाने के अलावा, एक आधार यह रहा है कि कुलपति इस तरह का आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं थे और किसी कॉलेज को संबद्धता देना अकादमिक परिषद/कार्यकारी परिषद का विशेषाधिकार है।

दलीलों के दौरान, इस न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 12 जनवरी, 2001 को एक आदेश पारित किया, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित किए जा रहे संस्थान को संबद्धता प्रदान करने के संबंध में निर्णय शैक्षणिक परिषद/कार्यकारी परिषद द्वारा लिया जाए और याचिकाकर्ताओं के मामले के संबंध में निर्णय न्यायालय के समक्ष रखा जाए। उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, मामले का निर्णय कार्यकारी परिषद द्वारा किया गया था। इस न्यायालय की प्रवेश पीठ द्वारा 12 जनवरी, 2001 को पारित अंतरिम आदेश की सूचना देना उचित होगा, जो इस प्रकार हैः -

"याचिकाकर्ता, अन्य बातों के साथ-साथ, 7 अगस्त, 2000 के आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा विधि अध्ययन संस्थान को संबद्धता प्रदान करने की उसकी याचिका प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय द्वारा खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि आदेश (जिसकी एक प्रति अनुलग्नक पी-21 के रूप में प्रस्तुत की गई है) को रद्द किया जाए और अकादमिक सत्र 2000-01 से प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाए ।

तर्कों के दौरान, यह हमारे संज्ञान में आया है कि संबद्धता के अनुदान के लिए आवेदन पर अकादमिक परिषद और विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा विचार किया जाना है। वर्तमान मामले में, विश्वविद्यालय के वकील द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि इस मामले पर न तो अकादमिक परिषद द्वारा और न ही कार्यकारी परिषद द्वारा विचार किया गया है। जहाँ तक अकादमिक परिषद का संबंध है, उसने निर्णय लेने के लिए फाइल को केवल कुलपति को भेज दिया था। यह अपने दिमाग को लागू करने में विफल रहा है। इसके बाद, इस मामले को कभी भी कार्यकारी परिषद के समक्ष नहीं रखा गया। अंतिम निर्णय डीन कॉलेज विकास परिषद द्वारा सूचित किया गया है। उनके पास मामले का फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

श्री जसकीरत सिंह का कहना है कि यह निर्णय वास्तव में कुलपति द्वारा लिया गया है। भले ही ऐसा हो, कुलपति के पास मामले पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इस मामले पर अकादमिक परिषद और कार्यकारी परिषद द्वारा विचार किया जाना था।

जिस तरह से विश्वविद्यालय ने अभी तक इस मामले से निपटा है, उससे हम बहुत खुश नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले में अनावश्यक रूप से देरी की गई है। अब हम प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय को इस मामले को विचार के लिए अकादमिक परिषद के समक्ष रखने का निर्देश देते हैं। इसके बाद मामले को अंतिम निर्णय के लिए कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

हम ये निर्देश प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड-1 के क़ानून 38 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जारी कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए कॉलेजों/संस्थानों के प्रवेश के लिए शर्त निर्धारित करता है। अंतिम निर्णय सुनवाई की अगली तारीख को न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

23 फरवरी, 2001 को आने के लिए।

आदेश की प्रति सामान्य शुल्क के भुगतान पर पक्षों के वकील को दस्ती दी जाए।

Sd/- जवाहर लाई गुप्ता,
न्यायाधीश

Sd/- N.K. सूद,
न्यायाधीश।

13. माननीय पीठ ने कहा कि मामले में अनावश्यक रूप से विलंब किया गया है और अकादमिक परिषद/निष्पादन परिषद द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को प्रस्तुत करने के लिए, मामले को 23 फरवरी, 2001 तक स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आदेश का अनुपालन काफी देरी के बाद फिर से किया गया था और कार्यकारी

परिषद द्वारा याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज करने वाले 16 फरवरी, 2001 के आदेश को अदालत की फाइल में रखा गया था। एक तकनीकी आपत्ति ली गई कि कार्यकारी परिषद द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए न तो कोई अनुरोध किया गया है और न ही कोई आधार उठाया गया है। इस संबंध में एक नागरिक विविध सं. 2001 का 9660 दायर किया गया था जिसकी अनुमति दी गई थी और याचिकाकर्ताओं को कार्यकारी परिषद के आदेश के खिलाफ अतिरिक्त आधार उठाने की अनुमति दी गई थी। रिट याचिका को 16 मई, 2001 को स्वीकार किया गया था और मामले को एकल पीठ के समक्ष नियमित सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था। इसके अनुसरण में, मामले की सुनवाई 5 जुलाई, 2001 को की गई। सुनवाई के दौरान, यह आवश्यक महसूस किया गया कि अतिरिक्त आधार उठाने के लिए प्रवेश पीठ द्वारा दी गई अनुमति को देखते हुए संशोधित याचिका दायर की जानी चाहिए। संशोधित याचिका दायर की गई थी, उसमें बयान प्रस्तुत किया गया था और इसी तरह प्रतिकृति भी।

14. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि कार्यकारी परिषद ने न तो अपना दिमाग लगाया है और न ही एक विवेकपूर्ण आदेश पारित किया है और जो आपत्तियां उठाई गई हैं वे अर्थहीन हैं और टिकाऊ नहीं हैं। वास्तव में, कार्यकारी परिषद ने अकादमिक परिषद की सिफारिशों को दोहराया है, जिन्हें 6 फरवरी, 2001 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प संख्या 22 के रूप में दर्ज किया गया है।

15. विद्वान वकील ने दो निरीक्षण समितियों द्वारा प्रस्तुत दो निरीक्षण रिपोर्टों, दिनांक 24 मार्च, 2000 और 4 अप्रैल, 2000, के संबंध में कार्यकारी परिषद की कथित चर्चा को लेते हुए तर्कों को संबोधित किया है।

16. यह तर्क दिया जाता है कि जहां तक अवसंरचना का संबंध है, निरीक्षण समिति की रिपोर्ट, दिनांक 15 जुलाई, 2000, के साथ

तुलना करने पर यह निर्णय योग्य नहीं है कि कार्यकारी परिषद द्वारा इस प्रकार की चर्चा कहाँ से की गई है। मेरा ध्यान निरीक्षण समिति द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है। सिफारिशें करते समय समिति द्वारा यह स्पष्ट रूप से राय दी गई है कि प्रस्तावित संस्थान/ कॉलेज ऑफ लॉ को LL.B का लॉ कोर्स पांच साल के पाठ्यक्रम का भाग I और तीन साल के पाठ्यक्रम का भाग I वर्तमान शैक्षणिक सत्र i.e 2000-2001 से प्रभावी M.D. विश्वविद्यालय की कॉलेज शाखा के साथ उपलब्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पहले से ही अनुमोदित प्रत्येक पाठ्यक्रम में 80 सीटों की संख्या के लिए, शुरू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं मिली हैं। एक अलग निष्कर्ष पर आने के लिए अधिकारियों ने कोई कारण नहीं दिया गया है। यह ध्यान देने योग्य होगा कि स्थायी लॉ कॉलेज के आवास के लिए भवन निर्माणाधीन है और इसे निरीक्षण समिति के संज्ञान में लाया गया था और यह कि वर्तमान भवन स्वीकार्य रूप से एस्बेस्टस शीट/छत के साथ एक अस्थायी भवन है। निरीक्षण समिति ने स्वयं देखा कि अस्थायी भवन संस्थागत/औद्योगिक क्षेत्र में स्थित D.A.V. महाविद्यालय के करीब है। यह अवलोकन करना उचित होगा कि D.A.V. कॉलेज को M.D. विश्वविद्यालय द्वारा बहुत पहले संबद्धता प्रदान की गई है। यह समझ में नहीं आता है, अगर D.A.V कॉलेज में छात्रों को पढ़ाने के लिए वातावरण अनुकूल है, लेकिन लॉ कॉलेज के छात्रों को पढ़ाने के लिए अनुकूल नहीं है। अतः निष्पादन परिषद की टिप्पणियों का कोई अर्थ नहीं है। स्थायी नए भवन के संबंध में किसी भी स्तर पर कोई आपत्ति नहीं की गई है, जो अंततः लॉ कॉलेज का घर है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस अदालत को सूचित किया है कि इस भवन के जुलाई, 2002 तक पूरा होने की संभावना है।

17."संकाय" (शिक्षण कर्मचारी) के संबंध में कार्यकारी परिषद के अवलोकन को भी याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा चुनौती

दी गई है। यह तर्क दिया गया है कि विज्ञापन में विभिन्न विषयों में व्याख्याताओं के पदों पर नियुक्त होने के लिए उम्मीदवारों को बुलाने के लिए समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। साक्षात्कार का विज्ञापन "वॉक-इन-इंटरव्यू" के रूप में किया गया था, जो 2 अगस्त, 2000 को आयोजित होने वाला था। "वॉक-इन-इंटरव्यू" के अनुसार संकाय कर्मचारियों की पहचान तदनुसार की गई थी और पहचाने गए कर्मचारियों के साथ एक संचार M.D. विश्वविद्यालय को भेजा गया था। यह समझ में नहीं आता कि कार्यकारी परिषद फरवरी, 1999 के विज्ञापन का संदर्भ कैसे दे रही है और 3 अगस्त, 2000 को की गई कर्मचारियों की नवीनतम पहचान को नजरअंदाज कर रही है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह भी बताया गया है कि कर्मचारियों की पहचान की जा सकती है, लेकिन विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में उनका चयन नहीं किया जा सकता है और एक प्रतिनिधि की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा अनंतिम/अंतिम संबद्धता प्रदान किए जाने के बाद ही की जा सकती है। शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में अवलोकन केवल एक उद्देश्य के साथ किया गया है i.e याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को अस्वीकार करना। यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां तक शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में निरीक्षण समिति की टिप्पणियों का संबंध है, वे सकारात्मक हैं और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में हैं। जहाँ तक पाँच साल के पाठ्यक्रम के संबंध में लॉ कॉलेज के लिए व्याख्याताओं के पद का संबंध है, एक विज्ञापन बनाया गया था और "वॉक-इन-इंटरव्यू" उपरोक्त के रूप में आयोजित किया गया था और कर्मचारियों की विधिवत पहचान की गई थी, जिसका कार्यकारी परिषद द्वारा बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है।

18. जहां तक गैर-शिक्षण कर्मचारियों का संबंध है, यह निर्णय योग्य नहीं है कि कहां से कार्यकारी परिषद ने स्वयं को अवगत कराया है कि गैर-शिक्षण कर्मचारी विश्वविद्यालय परिषद की निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते हैं। जबकि, इसके विपरीत, निरीक्षण

समिति ने 15 जुलाई, 2000 की अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अधिकांश उम्मीदवार योग्यता को पूरा करते हैं। गैर-शिक्षण पदों के लिए चयन के लिए पहचाने गए उम्मीदवार, U.G.C और M.D. विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा निर्धारित मानदंडों और योग्यताओं को पूरा करते हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अवलोकन जहरीले हैं। जहां तक निरीक्षण समिति की सिफारिशों का संबंध है, प्रथम समिति द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है, लेकिन दूसरी समिति ने इस संबंध में स्पष्ट सिफारिशें की हैं, लेकिन कार्यकारी परिषद द्वारा इसकी अनदेखी की गई है।

19. यह अजीब बात है कि कार्यकारी परिषद ने विशिष्ट शीर्षों के तहत विभिन्न मदों पर चर्चा करते समय प्रथम निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों का संदर्भ दिया है, लेकिन दूसरी निरीक्षण समिति द्वारा सकारात्मक टिप्पणियों का उल्लेख नहीं किया है। पिछली निरीक्षण समिति की सिफारिशों को आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया है, कार्यकारी परिषद का ऐसा दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर समाज को एक स्वस्थ संदेश नहीं भेजता है।

20. दूसरी निरीक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर चर्चा करते समय, दूसरी निरीक्षण समिति द्वारा क्या टिप्पणियां की गई हैं, इस पर ध्यान दिए बिना फिर से शिथिल शब्दों में टिप्पणियां की गई हैं।

21. छात्रावास सुविधा से संबंधित अंतिम मद का उल्लेख किया गया है, जबकि, छात्रावास सुविधा की व्यवस्था करने का वादा किया गया है "-" जहां तक लड़कियों का संबंध है, परिसर किराए पर लेने के लिए 10 जुलाई, 2000 का समझौता निरीक्षण समिति के समक्ष रखा गया था और जहां तक लड़कों का संबंध है, प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के तुरंत बाद आवश्यकताओं के अनुसार आवास की व्यवस्था करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। यह अवलोकन किया गया है कि लड़कियों के छात्रावास के लिए समझौता दूसरे निरीक्षण से केवल पाँच दिन पहले किया गया था। क्या यह

संस्थान से संबद्धता को अस्वीकार करने के लिए एक उचित आधार बनाता है?

22. यह मेरे संज्ञान में लाया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, छात्रावास का प्रावधान अनिवार्य नहीं किया गया है और यदि कोई छात्रावास प्रदान किया जाता है, तो छात्रावास के प्रभारी शिक्षक को अलग से नियुक्त किया जाएगा। हालांकि, जहां तक लड़कों का संबंध है, अस्थायी संबद्धता प्रदान करते समय इस तरह की शर्तें लगाई जा सकती थीं, लेकिन स्थिति संबद्धता को अस्वीकार करने की गारंटी नहीं देती थी।

23. यह तर्क दिया गया है कि कार्यकारी परिषद द्वारा पारित आदेश के अंत में, अकादमिक परिषद की सिफारिश को संकल्प सं. 22 दिनांक 6 फरवरी, 2001 को अपनाया गया है, जबकि अकादमिक परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव में कोई ठोस कारण नहीं है। कार्यकारी परिषद द्वारा की गई टिप्पणियां 5 जुलाई, 2000 की दूसरी निरीक्षण समिति की रिपोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के बिल्कुल विपरीत हैं, जिसमें अस्थायी संबद्धता देने के लिए एक विशिष्ट सिफारिश की गई है। इस तथ्य की पूरी तरह से अनदेखी की गई है।

24. आगे यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में विश्वविद्यालय गुड़गांव में एक विधि महाविद्यालय स्थापित करना चाहता था, इसलिए बल्लभगढ़ (फ़रीदाबाद)में विधि महाविद्यालय की स्थापना के लिए याचिकाकर्ताओं को संबद्धता देने के विचार की सराहना या पसंद नहीं करता था। यह आशंका है कि जो न्यास महाविद्यालयों की स्थापना में सफल रहा है और रहेगा, वह स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित संस्थान की तुलना में शिक्षा का कहीं बेहतर मानक प्रदान करेगा।

25. यह भी तर्क दिया गया है कि आपत्ति पहली बार में ली गई थी कि सांविधिक रूप से संबद्धता केवल तभी दी जा सकती है जब संस्थान जिला मुख्यालय में स्थापित किया गया हो और बल्लभगढ़ जिला मुख्यालय नहीं है, यह आपत्ति अर्थहीन है क्योंकि बल्लभगढ़

फरीदाबाद की नगरपालिका सीमा के भीतर आता है और इसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य निरीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया गया था और स्वीकार किया गया था कि इस संबंध में याचिका पर लिखित बयान दाखिल करने के अलावा किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की है। इस प्रकार, याचिका योग्यता से रहित है और इसे एक धोखे के रूप में स्थापित किया गया है। याचिकाकर्ताओं के मामले में जानबूझकर देरी की गई है ताकि गुड़गांव में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विधि संस्थान याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित किए जाने वाले संस्थान के ऊपर से कूच कर सके।

26. दूसरी ओर प्रत्यर्थी का रुख बहुत ठोस और टिकाऊ नहीं है। हालांकि, पहली बार की गई याचिका में कहा गया है कि ऐसा कोई वैधानिक अधिकार नहीं है जो याचिकाकर्ताओं में अधिकार के रूप में संबद्धता की मांग करने के लिए निहित हो, इस प्रकार, वर्तमान याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है और इसलिए, खारिज किए जाने के योग्य है।

27. यह आगे कहा गया है कि अधिकार के मामले के रूप में परमादेश की मांग नहीं की जा सकती है। यह केवल उन मामलों में विवेकाधीन उपाय है जहां दावेदार यह बताने में सक्षम है कि वैधानिक कर्तव्य, जो सार्वजनिक प्रकृति का है, कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। प्रत्यर्थी का यह भी मामला है कि बलभगढ़ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है और इसके बजाय फरीदाबाद में लॉ कॉलेज की स्थापना के लिए उक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया है, इस प्रकार, कानून की नजर में कोई प्रमाण पत्र बार काउंसिल द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार, इसकी अनुपस्थिति में, संबद्धता को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया गया है।

28. प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय का यह भी निवेदन है कि नीति के रूप में विधि पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए किसी भी कॉलेज/संस्थान को

संबद्धता प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इसके समर्थन में 6 दिसंबर, 1999 को आयोजित अपनी बैठक में अकादमिक परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का संदर्भ दिया गया है और उक्त संकल्प 51 नंबर पर दर्ज किया गया है। इस तरह के प्रस्ताव का उद्देश्य है कि निजी या सरकारी महाविद्यालय/संस्थान को संबद्धता प्रदान करने से, यह कानूनी शिक्षा के मानक पर विवाद करेगा। एक बार संबद्धता दिए जाने के बाद, शिक्षा का स्तर नहीं रखा जाता है और धन अर्जित किया जाता है जो संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य बन जाता है। इस प्रकार, विश्वविद्यालय किसी भी निकाय को संबद्धता देने में बहुत सतर्क था। आरोप है कि देश में कानूनी शिक्षा के मानक को बनाए रखने के लिए जनहित में संबद्धता को अस्वीकार कर दिया गया था। इस प्रकार, याचिका केवल इसी संक्षिप्त आधार पर खारिज होने के योग्य है।

29. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है। मुझे डर है, मैं प्रतिवादी के विद्वान वकील के तर्कों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूं। 15 जुलाई, 2000 की दूसरी निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के अवलोकन पर, यह अवलोकन करना उचित है कि याचिकाकर्ताओं के मामले की सिफारिश समिति द्वारा M.D. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई गाइड-लाइन के अनुसार सभी पहलुओं द्वारा अनंतिम संबद्धता प्रदान करने के लिए की गई है। विश्वविद्यालय की दलीलें बहुत कमजोर हैं और 16 फरवरी, 2001 के आरोपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि एक बहुत ही लापरवाह और सरसरी दृष्टिकोण अपनाया गया है। वास्तव में, ऐसा लगता है कि दिमाग का कोई अनुप्रयोग नहीं किया गया है। कार्यकारी परिषद द्वारा किए गए अवलोकन के साथ विभिन्न शीर्षों के तहत दूसरी निरीक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिशों की तुलना से पता चलता है कि दूसरी समिति की रिपोर्ट और रिपोर्टों का उल्लेख करने के अलावा उन पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। हालांकि, भले ही पूरी करने योग्य कमियों को उजागर किया जाता है, इसे अस्थायी संबद्धता देने के लिए शर्त

पूर्ववर्ती बनाया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि ऐसी शर्तों को एक समय सीमा में लागू किया जाना चाहिए जो संभव नहीं हो सकता है। दृष्टिकोण रचनात्मक और सकारात्मक होना चाहिए। कोई भी संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवित नहीं रह सकता है। यह याद रखना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थान बड़े पैमाने पर समाज के लिए होते हैं, लेकिन जब विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया गया रवैया जनहित से बहुत दूर होता है, तो कोई भी संस्थान जीवित नहीं रह सकता है और समाज के लिए सहायक नहीं हो सकता है। यदि अस्थायी संबद्धता दी जाती है, तो यह संस्थान को मानदंडों और लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करने और इसे केवल एक दुकान बनाने का लाइसेंस नहीं देगा। विश्वविद्यालय के पास इस तरह के संस्थानों को असंबद्ध करने के सभी अधिकार हैं। हालांकि, शुरुआत में इस तरह के दृष्टिकोण की न तो अनुमति दी जानी चाहिए और न ही इसे अपनाया जाना चाहिए। विवादित आदेश का अवलोकन बल्लभगढ़ (फ़रीदाबाद) में स्थापित किए जाने वाले लॉ कॉलेज को संबद्धता देने के याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए उचित कारण नहीं दर्शाता है।

30. याचिका, कि अकादमिक परिषद ने किसी भी निजी या सरकारी संस्थाओं को संबद्धता नहीं देने का निर्णय लिया है, को बहुत गंभीरता से स्वीकार नहीं किया गया है, जैसा कि आरोपित आदेश से ही स्पष्ट है। उक्त आदेश के अंतिम पैराग्राफ से पता चलता है कि परिषद ने दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं किए हैं। यह देखा गया है कि प्रस्तावित संस्थान केवल अगले शैक्षणिक सत्र से शिक्षण शुरू कर सकता है, जिसके लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है । यह संकल्प लिया गया है कि न्यास अगले शैक्षणिक सत्र के लिए संबद्धता के लिए फिर से आवेदन कर सकता है और निरीक्षण समिति फिर से दौरा कर सकती है और अपनी विशिष्ट सिफारिश दे सकती है। यह अजीब बात है कि दूसरी समिति द्वारा की गई सिफारिशें जो स्वयं

व्याख्यात्मक हैं, उन्हें सिफारिश के रूप में नहीं पढ़ा जा रहा है। यदि अकादमिक परिषद का निर्णय गंभीरता से होता कि अब से कोई अन्य निजी कॉलेज/संस्थान संबद्ध नहीं होगा, तो ऐसा अवलोकन, जैसा कि ऊपर देखा गया है, कार्यकारी परिषद द्वारा नहीं किया जाता। समापन पैरा पर ध्यान देना उचित होगा जो इस प्रकार हैः-

"परिषद ने यह भी कहा कि प्रस्तावित संस्थान अब केवल अगले शैक्षणिक सत्र से शिक्षण शुरू कर सकता है जिसके लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। इस प्रकार परिषद ने आगे निर्णय लिया कि यदि न्यास अगले शैक्षणिक सत्र के लिए संबद्धता के लिए आवेदन करता है, तो निरीक्षण समिति फिर से दौरा कर सकती है और अपनी विशिष्ट और स्पष्ट सिफारिश कर सकती है।"

31. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को अनुमति दी गई है और यह कि कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2000 के आदेश (प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-21) के अधिक्रमण में पारित दिनांक 16 फरवरी, 2001 (प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-22) जिसे कुलपति द्वारा पारित किए जाने का अनुमान लगाया गया है, को रद्द किया जाता है। अकादमिक परिषद और कार्यकारी परिषद को निर्देश दिया गया है कि वे इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर 15 जुलाई, 2001 की दूसरी निरीक्षण समिति की रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-19 की प्रतिलिपि) को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर विचार करें। अकादमिक परिषद/कार्यकारी परिषद उपरोक्त अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं से कोई भी जानकारी/स्पष्टीकरण मांगने के लिए स्वतंत्र होगी। इस प्रकार लिए गए निर्णय के बारे में याचिकाकर्ताओं को सूचित किया जाएगा। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर सत्र 2001-2002 के लिए विचार किया जाएगा।

32. इस निर्णय को देने से पहले यह देखा गया है कि संस्थानों को संस्थानों की तरह चलना चाहिए। उन संस्थानों से बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमने हमेशा उन शैक्षणिक संस्थानों को उच्च सम्मान दिया है जो हमारा इतिहास हैं, लेकिन यह आत्म-विनाशकारी दृष्टिकोण से निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सदियों पुराना तथ्य है कि बच्चे की पहली शिक्षिका मां होती है और संस्थानों को भी हर बच्चे के लिए मां की तरह व्यवहार करना चाहिए और जहां तक बच्चों की जरूरतों का संबंध है, "मां" कभी भी विफल नहीं हो सकती है।

33. दोनों पक्षों के खिलाफ समय सीमा की बाधाओं के कारण, यह निर्देश दिया जाता है कि इस न्यायालय के विशेष सचिव के हस्ताक्षर के तहत इस निर्णय की एक प्रमाणित प्रति आज पक्षों के विद्वान वकील को अनुपालन के लिए संबंधित तिमाहियों में प्रेषित करने के लिए दी जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
बिलासपुर,यमुनानगर

R.N.R.

जवाहर लाल गुप्ता से पहले, एन.के. सूद और अशुतोश

मोहुनता, *जे जे*

INCOME TAX, ROHTAK, – का कमिशनर
अपीलकर्ता

बनाम

एसएमटी। ARUNA *LUTHRA,–उत्तरदाता*

I.T.A. नहीं. 2000 का 2

31 अगस्त 2001

आयकर अधिनियम, 1961 – S.154 – अधिकारी का आकलन करना चिट फंड – में नुकसान की कटौती के बाद असेसी द्वारा दायर रिटर्नआदेश के सुधार के लिए कार्यवाही शुरू करने वाले अधिकारी का आकलन करना चिट फंड में नुकसान के कारण कटौती के लिए गधे के दावे को खारिज करके मूल्यांकन पर *द्वारा दिए गए निर्णय का आधार न्यायिक उच्च न्यायालय – क्या राजस्व आह्वान करने का हकदार है मूल्यांकन की कार्यवाही पूरी होने के बाद धारा 154 के प्रावधान – हेल्ड, हाँ, के सुधार के लिए कार्यवाही ए गण क्षेत्राधिकार द्वारा पारित आदेश के आधार पर शुरू किया जा सकता है उच्च न्यायालय या आदेश के बाद सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करें प्राधिकरण द्वारा पारित.*

हेल्ड, केवल मृतकों की कोई गलती नहीं है. से छूट त्रुटि नश्वर का विशेषाधिकार नहीं है. इसे ठीक न करना मूर्खतापूर्ण होगा. प्राधिकरण को सक्षम करने के लिए सेक्टियोइन 154 को अधिनियमित किया गया प्रतीत होता है